अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 में 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान

***

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम केन्द्रीय बजट संसद में पेश किया

***

अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जा रहा है जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा

***

राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान

***

देश में एफडीआई प्रवाह वर्ष 2014-2023 के दौरान 596 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ जो वर्ष 2005-2014 के दौरान हुए एफडीआई प्रवाह का दोगुना है

***

'गरीबों', 'महिलाओं', 'युवाओं', और 'अन्नदाताओं' का उत्थान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

***

युवाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ ही एक लाख करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा

***

पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना इस वर्ष जारी रखी जाएगी, कुल परिव्यय 1.3 लाख करोड़ रुपये का होगा

***

सरकार विकास के प्रति ऐसी अवधारणा पर काम कर रही है जो सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है

***

बजट में ऐसी अनेक घोषणाएं और रणनीतियां हैं जिनसे देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के निर्देशों और विकास अवधारणा के बारे में संकेत मिलता है

***

सरकार पूर्वी क्षेत्र और वहां के लोगों को भारत के विकास में अत्यंत मददगार बनाने पर अत्यधिक ध्यान देगी

***

सरकार आबादी में तेजी से हो रही वृद्धि और जनसंख्या में आए बदलाव से उत्पन्न चुनौतियों पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन करेगी

***

अंतरिम बजट में कर दरों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है

***

स्टार्ट-अप्स के साथ-साथ सॉवरेन वेल्थ या पेंशन फंडों द्वारा किए गए निवेश पर विशेष कर लाभ की अवधि एक साल बढ़ाई गई

***

प्रत्यक्ष कर संबंधी विशेष छिटपुट और विवादित मांगों को वापस लेने से लगभग एक करोड़ करदाताओं के लाभान्वित होने की आशा

***

सरकार ‘वर्ष 2014 तक के आर्थिक हालात और मौजूदा स्थिति’ पर श्वेत पत्र लाएगी

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली...

भाग-ए सार

आज संसद में अंतरिम केन्द्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जा रहा है जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा।

उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर तीन गुना कर देने के परिणामस्वरूप देश में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर व्यापक गुणक प्रभाव पड़ रहा है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान, जिसे वित्त मंत्री के भाषण के साथ पेश किया गया, के अनुसार भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके साथ ही यह आरबीआई (दिसंबर 2023 में आयोजित इसकी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में) द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विकास अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर देने के अनुरूप भी है जो वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में दर्ज की गई दमदार विकास पर आधारित है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपनी दमदार मजबूती का प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही उल्लेखनीय वृहद आर्थिक तत्वों को बरकरार रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अक्टूबर 2023 में अपने विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत में अपने विकास अनुमान को संशोधित करके जुलाई 2023 के अनुमानित 6.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। यह ऐसे समय में भारत की दमदार आर्थिक क्षमता में पूरी दुनिया के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है जब वर्ष 2023 में वैश्विक विकास का अनुमान 3 प्रतिशत पर यथावत रहा है।

आईएमएफ के अनुसार भारत के वर्ष 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (बाजार विनिमय दर पर डॉलर में) बन जाने की प्रबल संभावना है और यह भी अनुमान लगाया गया है कि पांच वर्षों में वैश्विक विकास में भारत का योगदान 2 प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसके अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि विश्व बैंक, आईएमएफ, ओईसीडी, और एडीबी ने वर्ष 2024-25 में भारत में आर्थिक विकास दर क्रमश: 6.4, 6.3, 6.1, और 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ने से राजस्व संग्रह में तेज उछाल देखने को मिली है। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि जीएसटी संग्रह दिसंबर 2023 में 1.65 लाख करोड़ रुपये रहा है। दरअसल, सातवीं बार सकल जीएसटी राजस्व 1.6 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े के पार चला गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 30.80 लाख करोड़ और 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।

वित्त मंत्री ने एक प्रमुख घोषणा के तहत कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की योजना इस वर्ष जारी रखी जाएगी और कुल परिव्यय 1.3 लाख करोड़ रुपये होगा। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75000 करोड़ रुपये का प्रावधान इस वर्ष प्रस्तावित किया गया है, ताकि राज्य सरकारों की 'विकसित भारत' संबंधी उपलब्धियां आधारित सुधारों को लागू करने में आवश्यक सहायता दी जा सके।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, जैसा कि वित्त मंत्री के 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की गई है, के तहत राजकोषीय घाटे को कम करके वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से भी नीचे लाने का उल्लेख करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इसी मार्ग पर अग्रसर होते हुए राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

इसी तरह वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल और शुद्ध बाजार उधारियां क्रमश: 14.13 और 11.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है और ये दोनों ही वर्ष 2023-24 के दौरान आंकी गई सकल और शुद्ध बाजार उधारियों से कम होंगी।

अर्थव्यवस्था के कुछ चमकते बिंदुओं का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपये है जिसमें कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपये हैं। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपये

है। 30.03 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमान से कहीं ज्यादा रहने की आशा है जो देश में विकास की गति तेज रहने और अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण को दर्शाता है।

श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल और शुद्ध बाजार उधारियां क्रमश: 14.13 लाख करोड़ और 11.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और ये दोनों ही उधारियां वर्ष 2023-24 की तुलना में कम रहेंगी।

उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2023 तक की अवधि के दौरान देश में एफडीआई प्रवाह 596 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ है जो स्वर्णिम युग को दर्शाता है और जो वर्ष 2005-2014 के दौरान हुए कुल एफडीआई प्रवाह का दोगुना है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि देश में विदेशी निवेश को निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए हम 'पहले भारत को विकसित करो' की भावना के तहत अपने विदेशी साझेदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौतों पर बात कर रहे हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूरी दृढ़ता के साथ चार प्रमुख जातियों पर भरोसा करते हैं और इसके साथ ही इन पर फोकस करते हैं। चार प्रमुख जातियां ये हैं- गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। उन्होंने कहा कि इन सभी की जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं, उनका कल्याण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि जब वे तरक्की करते हैं तो देश तरक्की करता है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विस्तार से बताया कि इस सरकार ने विकास के प्रति मानवीय और समावेशी अवधारणा अपनाई है जो अत्यंत उल्लेखनीय है और इसके साथ ही यह 'गांव स्तर तक प्रावधान करने' की पिछली अवधारणा से बिल्कुल हटकर है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में चलाए गए विकास संबंधी कार्यक्रमों ने 'सभी के लिए आवास', '*हर घर जल*', 'सभी के लिए बिजली', 'सभी के लिए रसोई गैस', 'सभी के लिए बैंक खाते एवं वित्तीय सेवाओं' के जरिए रिकॉर्ड समय में हर परिवार एवं व्यक्ति को लक्षित किया है।

वित्त मंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि सरकार विकास के प्रति ऐसी अवधारणा के साथ काम कर रही है जो कि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। इसमें सभी जातियों के साथ-साथ समस्त स्तरों पर लोगों को कवर किया जाता है। उन्होंने कहा, ''हम वर्ष 2047 तक देश को '*विकसित भारत* ' बनाने की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के

लिए हमें देशवासियों की क्षमता बढ़ाने और इसके साथ ही उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है।"

उन्होंने यह भी बताया "इससे पूर्व, सामाजिक न्याय अधिकतर एक राजनीतिक नारा था। हमारी सरकार के लिए, सामाजिक न्याय एक प्रभावशील और आवश्यक शासन मॉडल है"।

वित्त मंत्री ने मेज ध्वनि के बीच घोषणा की कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में असीम सकारात्मक बदलाव आया है और भारत के लोग उम्मीद और आशावादिता के साथ भविष्य ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा "रोजगार और उद्यमशीलता के लिए और अधिक अवसरों के लिए स्थितियों का सृजन किया गया। अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई। विकास के लाभ व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचने आरंभ हो गए। देश को उम्मीद की नई भावना प्राप्त हुई"।

वित्त मंत्री ने बताया कि इन दस वर्षों मे "सबका साथ" के उद्येश्य के साथ सरकार नए 25 करोड़ लोगों की बहु आयामी निर्धनता से मुक्ति दिलाने मे सहायता की है और सरकार के प्रयास अब ऐसे सशक्त लोगों की ऊर्जा और उत्साह के साथ समन्वित हो रही है।

उन्होंने बताया कि पीएम मुद्रा योजना में उद्यमशीत आकांक्षियों के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपये के बराबर के 43 करोड़ ऋणों को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए हैं। अंतरिम बजट में कई घोषणाएं और कार्यनीतियाँ शामिल हैं जो 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करने के लिए दिशाओं और विकास दृष्टिकोण का संकेत देती हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं करते हुए कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र और इसके लोगों को भारत के विकास का एक शक्तिशाली वाहक बनाने के लिए पूरा ध्यान देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को अर्जित करने के निकट है तथा 2 करोड़ और घरों का निर्माण परिवारों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता की पूर्ति के

लिए किया जाएगा। इसी प्रकार रूफ़टॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने 38 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया और 10 लाख रोजगार का सृजन किया है। प्रधानमंत्री फॉर्मालाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजिज योजना ने क्रेडिट लिंकेज के साथ 2.4 लाख एसएचजी और 60,000 व्यक्तियों की सहायता की है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि हमारे तकनीकविद् युवकों के लिए यह एक स्वर्णिम युग होगा क्योंकि 50 वर्ष के ब्याज ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये के कॉर्पस की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कॉर्पस दीर्घकालिक वित्तपोषण या लंबी अवधि के पुनर्वित और निम्न या शून्य ब्याज दर उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि यह निजी क्षेत्र को भी सनराइज सेक्टरों में उल्लेखनीय रूप से अनुसंधान एवं नवोन्मेषण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

रेलवे के लिए, तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों – ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह संपर्क गलियारा और उच्च ट्रैफिक घनत्व गलियारा को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में रूपांतरित किया जाएगा जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम में बढ़ोतरी हो सके।

विमानन क्षेत्र में हवाई अड्डों की संख्या दोगुना वृद्धि से 149 हो गई है, जो आज देश में 517 नए मार्गों पर 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियों ने सक्रिय रूप से एक हजार से अधिक नए हवाई जहाजों के ऑर्डर दिए हैं।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की कि सरकार तेजी से बढ़ रही जनसंख्या और जन-सांख्यिकीय परिवर्तनों से पैदा हो रही चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श करने के लिए उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) का गठन करेगी जिसे 'विकसित भारत' के लक्ष्य के संबंध में व्यापक रूप से इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी सिफारिशें करने का अधिदेश दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि हम नई आकांक्षाओं, नई चेतनाओं और नए दृढ़ संकल्पों के साथ राष्ट्र के विकास के प्रति अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि हमारे देश व्यापक संभावनाओं और अवसरों को उपलब्ध करा रहा है। यह हमारा कर्तव्य काल है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले के दौर की हर चुनौती से हमारे आर्थिक प्रबंधन और शासन के बल पर निपटा गया है। इन प्रयासों ने हमारे देश को दृढ़ संकल्प के साथ प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा दिया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि यह हमारी सही नीतियों, सच्ची भावना और उचित निर्णयों के कारण संभव हुआ है। जुलाई के पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के हमारे लक्ष्य के लिए विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेगी।

भाग-ख सारांश

अंतरिम बजट में कराधान के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों की दरें यथावत रखी गई हैं। हालाकि कराधान में लगातार निरंतरता उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप और सावरेन वेल्थ या पेशंन फंड द्वारा किए गए निवेशों के लिए कुछ विशेष कर लाभों तथा कुछ आईएफसी यूनिटों की कतिपय आय पर छूट की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेना

श्रीमती सीतारमण ने करदाता सेवाएं बेहतर बनाने की घोषणा की जो 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बेहतर बनाने के लिए सरकार के कर विजन के अनुरूप हैं। बड़ी संख्या में छोटी-छोटी, गैर-सत्यापित, गैर समायोजित या विवादित प्रत्यक्ष कर मांग हैं, जो बहीखातों में लगातार लंबित हैं। इनमें से कई मांगें तो वर्ष 1962 से भी लंबे समय से मौजूद हैं। इनसे ईमानदार करदाताओं को परेशानी होती है और इनसे बाद के वर्षों में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न होती है। अंतरिम बजट में 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25000 हजार रुपए तक तथा वित्तीय वर्ष 2011 से 2014-15 तक से संबंधित 10000 रुपए तक की ऐसी बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है। इससे लगभग एक करोड़ करदाताओं के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

प्रत्यक्ष कर संग्रहण तीन गुणा

करदाताओं के समर्थन की प्रशंसा करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण तीन गुणा ने अधिक हुआ है और रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुणा बढ़ी है। उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि सरकार ने कर दरों में कटौती की है और उन्हें विवेकपूर्ण बनाया है, जिसके कारण नई कर योजना के तहत अब 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि खुदरा व्यापारियों के साथ-साथ पेशेवरों के लिए पूर्वानुमान कराधान की सीमा बढ़ाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा स्वदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर दरों को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत तथा कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत कर दिया गया है। अपने अंतरिम बजट भाषण में उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में सरकार का फोकस बेहतर करदाता सेवाओं पर रहा है, जिसने सदियों पुरानी क्षेत्राधिकार आधारित निर्धारण प्रणाली को बदल दिया है और आयकर विवरणियों को दाखिल करना बहुत आसान और सरल बना दिया है। आयकर रिटर्न का औसत प्रोसेसिंग समय जो वर्ष 2013-14 में 93 दिन था अब घटकर इस वर्ष केवल 10 दिन रह गया है। इस प्रकार रिफंड जारी करने में तेजी आई है।

जीएसटी ने अनुपालन बोझ कम किया

अप्रत्यक्ष करों के बारे में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी ने भारत में बहुत बंटी हुई अप्रत्यक्ष व्यवस्था को एकीकृत करके उद्योग और व्यापार पर अनुपालन बोझ कम किया है। एक अग्रणी परामर्शदाता फर्म द्वारा अभी हाल में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार यह बताया गया है कि 94 प्रतिशत उद्योग प्रमुख जीएसटी में हुए परिवर्तन को व्यापक रूप से सकारात्मक मानते हैं। अपने अंतरिम बजट भाषण में उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि जीएसटी का कराधान बढ़कर दोगुने से अधिक हो गया है और औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण इस वर्ष लगभग दोगुणा बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे राज्यों को भी लाभ मिला है। राज्यों को जारी किए गए मुआवजे सहित राज्यों के एसजीएसटी राजस्व का तेज उछाल वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक जीएसटी के बाद की अवधि में 1.22 रहा है। उन्होंने कहा कि इसके सबसे बड़े लाभार्थी उपभोक्ता हैं क्योंकि लॉजिस्टिक लागत और करों में कटौती से अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में कमी आई है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए सीमा शुल्क में किए गए अनेक उपायों का उल्लेख करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि

इनके परिणामस्वरूप वर्ष 2019 से पिछले चार वर्षों की तुलना में इनलैंड कंटेनर डिपो में आयात निर्गम समयावधि 47 प्रतिशत कम होकर 71 घंटे रह गए हैं और एयर कार्गो परिसरों में 28 प्रतिशत कम होकर 44 घंटे तथा बंदरगाहों 27 प्रतिशत कम होकर 85 घंटे रह गई है।

श्वेत पत्र जारी करना

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में चरण-दर-चरण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और शासन प्रणाली को उचित मार्ग पर लाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास का सफलतापूर्ण अनुकरण करते हुए सरकार द्वारा पूरा किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उन वर्षों का संकट दूर कर दिया गया है और अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास के साथ एक उच्च सतत विकास मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं विषय पर श्वेत पत्र के साथ आगे आएगी, जिसका केवल एक ही उद्देश्य है कि उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीखा जा सके।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई -3

अंतरिम बजट – 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

अंतरिम बजट 2024-25 की मुख्य बातें

****

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली --------

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र और 'सबका प्रयास' के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में आज अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

भाग – क

सामाजिक न्याय

- चार प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता (किसान) को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस।

'गरीब कल्याण, देश का कल्याण'

- पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की।
- पीएम-जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।

- पीएम-स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता। 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ।
- पीएम-जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के विकास पर जोर।
- पीएम-विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड-टू-एंड मदद।

'अन्नदाता' का कल्याण

- पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- पीएम-फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई।
- इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट (ई-नाम) के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद-फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध।

नारी शक्ति पर जोर

- 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए।
- उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ा।
- स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43 प्रतिशत नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है।
- पीएम-आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण)

- कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा।
- अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा।

छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और निशुल्क बिजली

- छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे।
- हरेक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का अनुमान।

आयुष्मान भारत

- आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण

- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली है।

आर्थिक उन्नति रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार

- 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।

बुनियादी ढांचा

- बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगी।

रेलवे

- लॉजिस्टिक्स कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है।
    - ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा
    - पत्तन संपर्कता गलियारा
    - अधिक यातायात वाले गलियारा
- 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को 'वंदे भारत' मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।

विमानन क्षेत्र

- देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई दोगुनी।
- 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं।
- देश की विमानन कंपनियों ने 1,000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए।

हरित ऊर्जा

- वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी।
- परिवहन के लिए कम्प्रस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) में कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र

- राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पर्यटन केन्द्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा।
- इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा।

निवेश

- वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतर्प्रवाह 596 अरब डॉलर रहा, जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान हुए एफडीआई अंतर्प्रवाह के मुकाबले दोगुना है।

'विकसित भारत' के लिए राज्यों में सुधार

- राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव।

संशोधित अनुमान (आरई) 2023-24

- उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपए है जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ रुपए है।
- कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपए है।
- 30.03 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और इसके औपचारीकरण को दर्शाता है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 5.8 प्रतिशत है।

बजट अनुमान 2024-25

- उधारी से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
- राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी।
- वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- वर्ष 2024-25 के दौरान डेटेड सिक्योरिटीज़ के जरिए सकल एवं शुद्ध बाजार उधारी क्रमश: 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान।

भाग - ख

प्रत्यक्ष कर

- वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया
- पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी
- सरकार करदाता सेवाओं में लाएगी सुधार
    - वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा
    - वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा
    - इससे एक करोड़ करदाताओं को होगा लाभ
- सावरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश, स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31.03.2025 तक बढाया गया
- आईएफएससी इकाईयों की कुछ आय पर कर रियायत को एक साल बढ़ाकर 31.03.2024 से 31.03.2025 किया गया

अप्रत्यक्ष कर

- वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बकरार रखने का प्रस्ताव किया
- जीएसटी ने देश में पूरी तरह बिखरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया
    - इस साल औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपये हुआ
    - जीएसटी कर आधार दोगुना हुआ
    - राज्यों का राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि अनुपात (राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति सहित) जीएसटी से पहले की अवधि (2012-13 से 2015-16) के 0.72 से बढ़कर जीएसटी लागू होने के बाद की अवधि (2017-18 से 2022-23) के दौरान 1.22 हो गया
    - उद्योग जगत के 94 प्रतिशत उद्यमियों के अनुसार जीएसटी व्यवस्था काफी कुछ सकारात्मक रही है

- जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला युक्तिसंगत बनी
- जीएसटी से व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ कम हुआ
- लॉजिस्टिक लागत और करों में कमी से वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटने से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा

पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के प्रयास

- वित्त वर्ष 2013-14 में जहां 2.2 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त थी, वहीं अब सात लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देनदारी नहीं।
- खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया
- पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया गया
- वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की गई
- विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर कर दर 15 प्रतिशत रखी गई

करदाता सेवाओं की उपलब्धियां

- कर रिटर्न प्रोसेस करने की औसत समय-सीमा 2013-14 के 93 दिन से घटकर दस दिन रह गई
- बेहतर दक्षता के लिए चेहरा रहित आकलन और अपील की शुरूआत की गई
- रिटर्न दाखिल करने के काम को सरल बनाने के लिए नया 26 एएस फार्म और पहले से भरे गये टैक्स रिटर्न विवरण के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अद्यतन किया गया
- सीमा शुल्क सुधारों से आयतित माल छोड़ने के समय में आई कमी
  - अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में यह 47 प्रतिशत घटकर 71 घंटे रह गया
  - एयर कार्गो परिसरों में यह 28 प्रतिशत घटकर 44 घंटे रह गया
  - समुद्री बंदरगाहों पर 27 प्रतिशत घटकर 85 घंटे रह गया

अर्थव्यवस्था - तब और अब

- वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था में सुधार और प्रशासन प्रणाली को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी थी। तब समय की जरूरत थी:
    - निवेश आकर्षित करना
    - बहुप्रतीक्षित सुधारों के लिए समर्थन जुटाना
    - लोगों में उम्मीद जगाना
- सरकार 'राष्ट्र प्रथम' की मजबूत भावना के साथ सफल रही
- ''अब यह देखने का उचित समय है कि 2014 तक हम कहां थे और अब कहां है'' वित्त मंत्री

सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर एक श्वेत-पत्र रखेगी

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई-26

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी; इसे 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है

***

राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023-24 (आरई) में जीडीपी का 5.8 प्रतिशत रहेगा, यह 2024-25 में जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान

***

वर्ष 2024-25 में कुल व्यय वर्ष 2023-24 (आरई) की तुलना में 2.76 लाख करोड़ रुपये बढ़ाया गया, यह 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान

***

वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां ज्यादा रहने से विकास की गति तेज रहने और अर्थव्यवस्था में औपचारिकरण का संकेत मिलता है

***

केन्द्र सरकार की उधारियां कम रहने से निजी क्षेत्र के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ जाएगी

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली...

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए पूंजीगत व्यय, 2023-24 के संशोधित अनुमान और 2024-25 के बजट अनुमानों की रूपरेखा पेश की।

पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पिछले चार वर्षों में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को तीन गुना बढ़ा देने से देश में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर व्यापक गुणक प्रभाव पड़ रहा है।

संशोधित अनुमान 2023-24

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा, 'उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपये है जिनमें 23.24 लाख करोड़ रुपये की कर प्राप्तियां हैं। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपये है।'

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने राजस्व प्राप्तियों की चर्चा करते हुए कहा कि 30.03 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमान से अधिक रहने की आशा है, जो आर्थिक विकास की तेज गति और अर्थव्यवस्था में औपचारिकरण को दर्शाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान में कुछ कमी होने के बावजूद राजकोषीय घाटा का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.8 प्रतिशत रहा है, जो कि बजट अनुमान से बेहतर है।

बजट अनुमान 2024-25

वर्ष 2024-25 में उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसी तरह कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।

इसके अलावा, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा, 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की योजना इस वर्ष जारी रखी जाएगी और कुल परिव्यय 1.3 लाख करोड़ रुपये का होगा।'

श्रीमती सीतारमण ने कहा, 'राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।' राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर अडिग रहने, जैसा कि वर्ष 2021-22 के

उनके केन्द्रीय बजट भाषण में कहा गया था, की बात कहते हुए उन्होंने इसे वर्ष 2025-26 तक घटाकर जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का उल्लेख किया।

बाजार उधारियां

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल और शुद्ध बाजार उधारियां क्रमश: 14.13 लाख करोड़ रुपये और 11.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। निजी निवेश में वृद्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 'केन्द्र सरकार की उधारियां कम रहने से निजी क्षेत्र के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ जाएगी।'

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई -1

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

अंतरिम बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव यथावत

*

कुछ बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों में राहत से लगभग एक करोड़ करदाता लाभान्वित होंगे

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली...

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि कर प्रस्तावों के संबंध में परम्परा के अनुसार मैं कराधान के संबंध में किसी भी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं कर रही हूं। आयात शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कर दरें यथावत रखने का प्रस्ताव कर रही हूं।

कराधान में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री ने स्टार्टअप और सावरेन वेल्थ या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ आईएफएससी इकाईयों की आय पर कर छूट की समय सीमा 31.03.2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप जीवन की सुगमता और व्यापार करने में आसानी के लिए कर सेवा सुविधा में सुधारों की घोषणा की गई है। बड़ी संख्या में कई छोटी-छोटी गैर-सत्यापित, गैर-समायोजित या विवादित प्रत्यक्ष कर मांग बहीखातों में लंबित है, इनमें से कई मांगें वर्ष 1962 से से भी पहले की है। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25,000 रुपये तक और वर्ष 2010-11 से 2014-15 से संबंधित 10,000 तक की ऐसी

बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव किया है, इससे लगभग एक करोड़ करदाता लाभांवित होंगे।

**.*

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई/02

अंतरिम बजट - 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

एक करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम करने के लिए छत पर सौर प्रणाली लाई जाएंगी

***

सार्वजनिक परिवहन के लिए बड़े स्तर पर ई-बसों को भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा : वित्त मंत्री

***

पर्यावरण के अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराने के लिए जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली --------

सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के सरकार के दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। उन्होंने हरित विकास और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की।

छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और मुफ्त बिजली

वित्त मंत्री ने कहा कि छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री के लिए गए संकल्प के अनुसरण में लायी गई है। इससे अपेक्षित लाभ इस प्रकार हैं :

क. निःशुल्क सौर बिजली और बिजली वितरण कंपनियों को अधिशेष बिजली बेचने से परिवारों को हर वर्ष पंद्रह हजार से अठारह हजार रुपये की बचत;

ख. इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग;

ग. आपूर्ति और इन्स्टालेशन के लिए बड़ी संख्या में वेंडरों को उद्यमशीलता का अवसर;

घ. विनिर्माण, इन्स्टालेशन और रखरखाव में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर;

हरित ऊर्जा

वर्ष 2070 तक 'नेट-जीरो' को लेकर प्रतिबद्धता को पूरा करने के लक्ष्य के साथ श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 में निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव किया है :-

क. एक गीगा-वाट की शुरुआती क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को हासिल करने के लिए व्यवहार्यता अंतर-निधियन की व्यवस्था की जाएगी।

ख. वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथेनाल,स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस,मैथेनॉल और अमोनिया के आयात को कम करने में मदद मिलेगी।

ग. परिवहन के लिए कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप्डनेचुरल गैस (पीएनजी) में कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के चरणबद्ध तरीके से मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा।

घ. बायोमास के संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

विद्युत वाहन इकोसिस्टम

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए बड़े स्तर पर ई-बसों को भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार ई-वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान कर ई-वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी।‘

जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री

हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती सीतारमण ने जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह योजना प्राकृतिक रूप से सड़नशील बहुलक, जैव-प्लास्टिक, बायो-फार्मास्युटिकल्स और बायो-एग्री-इनपुट जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा, “यह योजना आज के उपभोगकारी विनिर्माण प्रतिमान को पुनःसर्जनात्मक सिद्धांतों पर आधारित विनिर्माण प्रतिमान में बदलने में भी मदद करेगी।”

****

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई-4

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

विपरीत भूराजनीतिक घटनाक्रमों से उपजी अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने गतिशीलता प्रदर्शित की और स्वस्थ वृहद आर्थिक बुनियादी कारकों को बनाए रखा

***

भारत के वास्तविक जीडीपी के वित्त वर्ष 2023-24 में 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान

***

भारत का राजकोषीय संघटन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना जारी, 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम करके 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा

***

11.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अगले वर्ष तक 11,11,111 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय परिव्यय

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली...

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि विपरीत भूराजनीतिक घटनाक्रमों और कोविड-19 महामारी के दौरान विस्तारित राजकोषीय कदमों से उपजी अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने गतिशीलता प्रदर्शित की और स्वस्थ वृहद आर्थिक बुनियादी कारकों को बनाए रखा। वित्त वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम आकलनों के अनुसार, भारत के वास्तविक जीडीपी के वित्त वर्ष 2023-24 में 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह जानकारी वृहद-आर्थिक संरचना वक्तव्य 2024-25 में दी गई।

पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर के साथ-साथ उपभोग एवं निवेश के लिए मजबूत घरेलू मांग को वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम छमाही में जीडीपी के प्रमुख वाहक के बीच देखा

जा रहा है। आपूर्ति पक्ष पर, उद्योग एवं सेवा पक्ष वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम छमाही के प्राथमिक विकास वाहक रहे। भारत ने इस अवधि के दौरान प्रमुख उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच सर्वोच्च वृद्धि दर दर्ज की। आईएमएफ के अनुसार, भारत के बाजार विनिमय दर पर डॉलर में वर्ष 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का अनुमान हैं। यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगले पांच वर्षों में वैश्विक विकास में भारत का योगदान 200 आधार अंकों तक बढ़ जाएगा।

यह देखते हुए कि पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय परिव्यय में तीन गुणा बढ़ोत्तरी किए जाने के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर व्यापक बहुगुणक प्रभाव पड़ा, केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने अगले वर्ष के लिए परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर ग्यारह लाख, ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह करोड़ रुपये (111.1 करोड़) करने के घोषणा की। आज संसद में अंतरिम 2024-25 को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी कि यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा। विकास की गति को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण की दिशा में बजट अनुमान में 1.3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया, जिससे कि राज्य अपने संबंधित पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दे सके। वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम इस वर्ष भी जारी रहेगी।

2014-23 के दशक को एफडीआई प्रवाह के लिए स्वर्ण युग करार देते हुए श्रीमती सीतारमण ने सदन को बताया कि इस अवधि के दौरान प्रवाह 2005-14 की संख्या के मुकाबले दोगुना था, जो 596 बिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि " निरंतर विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम" "फर्स्ट डेवल्प इंडिया" की भावना के साथ अपने विदेशी साझेदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं।

भारत की बाहरी स्थिति, विशेष रूप से चालू खाता घाटे में उल्लेखनीय कमी और एक आरामदायक विदेशी मुद्रा भंडार बफर की बदौलत पूंजीगत प्रवाह के पुनरुत्थान का परिणाम वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय रुपये में स्थिरता के रुप में सामने आया। इसके अतिरिक्त

वृहद -आर्थिक संरचना वक्तव्य 2024-25 में कहा गया कि सरकार द्वारा की गई सक्रिय आपूर्ति पक्ष पहलू के द्वारा भारत में मुद्रास्फीर्ति दबाव में काफी कमी आई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय परिदृश्य पर विचार करते हुए वित्त मंत्री ने कहा "2024-25 में राजकोषीय घाटा के जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जैसा कि 2021-22 के मेरे बजट भाषण में घोषणा की गई थी, हम 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहें हैं। मध्यकालिक राजकोषीय नीति व राजकोषीय नीति रणनीतिक वक्तव्य में कहा गया है कि इस प्रतिबद्धता के अनुरूप संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे के जीडीपी का 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि 5.9 प्रतिशत के 2023-24 के बजट अनुमान से कम है।

राजकोषीय संकेतक- जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बदलते लक्ष्य

	संशोधित अनुमान	**बजट अनुमान**
	2023-24	2024-25
1. राजकोषीय घाटा	5.8	5.1
2. राजस्व घाटा	2.8	2.0
3. प्राथमिक घाटा	2.3	1.5
4. कर राजस्व (सकल)	11.6	11.7
5. गैर कर राजस्व	1.3	1.2
6. केंद्र सरकार ऋण	57.8	56.8

(स्रोत: मध्यकालिक अवधि राजकोषीय नीति व राजकोषीय नीति रणनीतिक वक्तव्य)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं:

सरकार की राजकोषीय नीति का उद्येश्य बिना समग्र वृहद आर्थिक संतुलनों से समझोता किए बाहरी आघातों का सामना करने और वैश्विक आर्थिक मंदी के जोखिमों को कम करने के लिए

घरेलू अर्थव्यवस्था को अधिक गतिशील बनाना रहा है। सरकार की वित्त वर्ष 2024-25 राजकोषीय रणनीति निम्नलिखित व्यापक उदयेशों पर आधारित हैं:

क) अप्रत्याशित आघातों, अगर कोई हो, का अवशोषण करने के लिए अधिक समावेशी, टिकाऊ और अधिक गतिशील घरेलू अर्थव्यवस्था की दिशा में लक्षित

ख) अवसंरचना विकास गति को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय की दिशा में अधिक संसाधनों को मोड़ना तथा आबंटित करना

ग) पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों के प्रयासों में सहायता के द्वारा सार्वजनिक अवसंरचना बढ़ाने की दिशा में राजकोषीय संघवाद के समग्र दृष्टिकोण को जारी रखना

घ) पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों को अपनाते हुए, समेकित और समन्वित योजना निर्माण तथा देश में अवसंरचना प्रयोजनाओं के कार्यान्वयन पर फोकस

ङ) नागरिकों के दीर्घकालिक टिकाऊ और समावेशी बेहतरी के लिए प्रमुख विकासात्मक सेक्टरों अर्थात पेयजल, आवासन, स्वच्छता, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, प्रणाली आदि की दिशा में व्यय को प्राथमिकता देना

च) एसएनए/टीएसए आदि उपयोग के द्वारा संसाधनों के बिल्कुल ठीक समय पर जारी किए जाने के माध्यम से नकदी प्रबंधन की प्रवाहों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई -05

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

वित्त मंत्री ने नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहलों में निजी निवेश को बढावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के नए कॉर्पस को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया

***

"हमारे तकनीक प्रेमी युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा"- वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण

पचास वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण से एक लाख करोड़ रुपये का कॉर्पस स्थापित किया जाएगा

रक्षा क्षेत्र में गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और *'आत्मनिर्भरता'* में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव

नए युग की प्रौद्योगिकियां और डाटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहे हैं - वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली...

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहलों में निजी निवेश

को बढावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के नए कॉर्पस को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे तकनीक प्रेमी युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा।

पचास वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण से एक लाख करोड़ रुपये का कॉर्पस स्थापित किया जाएगा। इस कॉर्पस से दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नवोन्मेष बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। हमें ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे जो युवा शक्ति और प्रौद्योगिकी को जोड़े।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और *'आत्मनिर्भरता'* में तेजी लाने के लिए नई योजना का प्रस्ताव भी किया।

प्रौद्योगिकी में बदलाव

वित्त मंत्री ने कहा कि नए युग की प्रौद्योगिकियां और डाटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहे हैं। इन प्रौद्योगिकियों से नए आर्थिक अवसर भी संभव हो रहे हैं और 'सामाजिक संरचना के आखिरी पायदान' पर मौजूद लोगों सहित सभी लोगों को किफायती दरों पर उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल रही हैं।

वैश्विक स्तर पर भारत के लिए अवसरों के हो रहे विस्तार पर बात करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि, "भारत अपने लोगों की नई पहलों और उद्यमशीलता के माध्यम से समाधान दर्शा रहा है।"

अनुसंधान और नवाचार

आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नवाचार पर जोर देते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने *"जय जवान जय*

किसान" का नारा दिया था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे *"जय जवान जय किसान जय विज्ञान"* का नारा बना दिया।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस नारे का और विस्तार करते हुए इसे *"जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान"* बना दिया है क्योंकि नई पहल ही विकास का आधार है।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई -

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

<u>नारी शक्ति को प्रोत्साहन</u>

***

उद्यमशीलता, जीवन में सुगमता और गरिमा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को गति दी गई है: वित्त मंत्री

***

मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ ऋण दिए गए

***

उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ चुका है

***

STEM पाठ्यक्रमों के लिए होने वाले नामांकन में बालिकाओं और महिलाओं की भागीदारी 43 प्रतिशत- यह संख्या विश्व में सबसे ज्यादा

***

कार्यक्षेत्र में महिलाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी

***

तीन तलाक को गैर-कानूनी बनाया गया

****

लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गईं

****

ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए 70 प्रतिशत से अधिक मकान महिलाओं के नाम पर या उन्हें संयुक्त मालिकाना हक के तहत प्रदान किए गए

****

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा है कि उद्यमशीलता, जीवन में सुगमता और आत्म-सम्मान को बढ़ावा देने को लगातार प्रोत्साहन देकर महिलाओं के सशक्तिकरण को इन दस वर्षों में काफी बढ़ावा मिला है।

वित्त मंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 30 करोड़ ऋण प्रदान किए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा

के लिए महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। STEM पाठ्यक्रमों में 43 प्रतिशत नामांकन बालिकाओं और महिलाओं का हुआ है, यह संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इस तरह के सभी उपाय कार्यक्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के रूप में प्रतिबिंबित हो रहे हैं।

'तीन तलाक' को गैर-कानूनी बनाने और लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नाम पर या उन्हें संयुक्त मालिकों के रूप में 70 प्रतिशत से अधिक मकान उपलब्ध कराने के फलस्वरूप उनका आत्मसम्मान बढ़ा है।

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के दृढ़ विश्वास का उल्लेख करते हुए कहा है कि हमें चार प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ये जातियां हैं- 'गरीब', 'महिलाएं', 'युवा' और 'अन्नदाता'। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि उन लोगों की आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब वे उन्नति करते हैं तो देश की प्रगति होती है। इन चारों जातियों को अपना जीवनस्तर बेहतर बनाने के प्रयास में सरकार द्वारा सहायता की आवश्यकता है और उन्हें सरकार से सहायता मिल भी रही है। इन लोगों का सशक्तिकरण होने से और उनके कल्याण से देश भी आगे बढ़ेगा।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई-7-फाइनल

अंतरिम बजट – 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जाएगा: वित्त मंत्री

करीब एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में दी गई मदद

नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवेश में ला रहे बदलाव

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली --------

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए घोषणा की कि लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण सामाजिक-आ्रिथक परिवेश में बदलाव ला रहे हैं। इनकी सफलता से पहले ही करीब एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिल चुकी है। वे दूसरों के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्हें सम्मान देकर उनकी उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बढ़ाया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का यह पक्का विश्वास है कि हमें चार प्रमुख जातियों पर ध्यान देना चाहिए और ये जातियां हैं 'गरीब', 'महिलाएं', 'युवा' और 'अन्नदाता'। "उनकी जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब वे प्रगति करते हैं तो देश प्रगति करता है।" उन्होंने कहा कि सभी चारों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके सशक्तिकरण और कल्याण में सरकार के समर्थन की आवश्यकता होगी और यह उन्हें प्राप्त होगा, जिससे कि देश आगे बढ़ेगा।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है जोकि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। यह हर स्तर पर सभी जातियों और लोगों तक पहुंचेगा। सरकार 2047 तक देश को 'विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। "इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लोगों की क्षमता को बेहतर और उन्हें सशक्त बनाना होगा।"

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई-8

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर विशिष्ट पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा तय की जाएगी: केंद्रीय वित्त मंत्री

***

विशिष्ट पर्यटन केंद्रों के विकास से जुड़े वित्तपोषण के लिए राज्यों को दीर्घावधि के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे

***

लक्षद्वीप सहित विभिन्न द्वीपों पर बंदरगाह संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू होंगी

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए 2047 तक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए पर्यटन केंद्रों के समग्र विकास पर जोर दिया।

विशिष्ट पर्यटन केंद्र

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को विशिष्ट पर्यटन केंद्रों के समग्र विकास, वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और प्रचार के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए राज्यों को दीर्घावधि के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इन केंद्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के क्रम में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा तय की जाएगी, जो सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता पर आधारित होगी।

घरेलू पर्यटन

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का मध्यम वर्ग भी अब यात्रा और नए स्थलों की खोज का आकांक्षी है; और पर्यटन में स्थानीय उद्यमशीलता के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। इसमें आध्यात्मिक पर्यटन भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित विभिन्न द्वीपों पर बंदरगाह संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इससे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।

घरेलू पर्यटन के अलावा भारत की विविधता भी वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस संबंध में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि 60 स्थानों पर जी-20 बैठकों के सफल आयोजन से वैश्विक पर्यटकों के सामने भारत की विविधता प्रदर्शित हुई है। साथ ही, भारत की आर्थिक क्षमताओं ने इसे व्यवसाय और सम्मेलनों से जुड़े पर्यटन के लिहाज से एक आकर्षक स्थल बना दिया है।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई -9

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

अंतरिम बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र में मूल्य-वर्द्धन और किसानों की आय बढ़ाने का वादा किया

***

प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण और विपणन सहित फसल कटाई पश्चात की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की घोषणा

***

पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता

***

पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा

***

तिलहन के लिए 'आत्मनिर्भरता' को प्राप्त करने के लिए कार्यनीति बनाई जाएगी

***

सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण और ग्रामीण मांग को बढ़ाना अंतरिम बजट की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। किसानों को अपने 'अन्नदाता' बताते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि अन्नदाता के उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उचित रूप से समय-समय पर वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर वर्ष सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि अनेक दूसरे कार्यक्रमों के अलावा इन उपायों से 'अन्नदाता' को देश और पूरी दुनिया के लिए अन्न पैदा करने में

सहायता दी जा रही है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 80 करोड़ लोगों के लिए नि:शुल्क राशन के माध्यम से भोजन से जुड़ी चिंताओं को समाप्त कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्द्धन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाने का वादा किया गया है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए समावेशी, आधुनिक भंडारण, पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण एवं विपणन और ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के पश्चात की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को भविष्य में बढावा देने का वादा किया।

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि-क्षेत्र समावेशी, संतुलित, उच्चतर संवृद्धि और उत्पादकता की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को कृषक-केंद्रित नीतियां लाकर, किसानों को उनके आय अर्जन में सहायता देकर, कीमत और बीमा के माध्यम से जोखिम कवरेज देकर, स्टार्ट-अप के माध्यम से प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देकर सुगम किया गया है।

वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और साठ हजार व्यक्तियों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में सहायता मिली

है। वित्तमंत्री ने कहा कि फसल कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने और उत्पादकता एवं आमदनी बढ़ाने के प्रयासों में अन्य योजनाओं से मदद मिल रही है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है।

वित्तमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1361 मंडियों को एकीकृत कर दिया है और इसमें 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कारोबार हो रहा है एवं 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही हैं।

वित्तमंत्री ने कहा कि मूलभूत आवश्यकताओं के इन प्रावधानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक आय में वृद्धि की है। किसानों की आर्थिक आवश्यकताओं का समाधान निकाला है और इस प्रकार से यह उपाय कृषि क्षेत्र में निरंतर वृद्धि करते हुए रोजगारों का सृजन कर रहे हैं।

आत्मनिर्भर तिलहन अभियान

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के संबंध में *'आत्मनिर्भरता'* प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीकों को व्यापक पैमाने पर अपनाने, बाजार संपर्कों, खरीद, मूल्य-वर्धन और फसल बीमा को शामिल किया जाएगा।

नैनो डीएपी

केंद्रीय वित्तमंत्री ने अपने संभाषण में कहा कि नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी को अपनाया जाएगा।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई/10

अंतरिम बजट – 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

खेलों में हमारे युवाओं द्वारा नई ऊंचाईयों को छूने से देश गौरवान्वित: केन्द्रीय वित्त मंत्री

****

बजट में युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित करने का प्रस्ताव

****

तकनीकी प्रेमी हमारे युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा : श्रीमती निर्मला सीतारमण

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली --------

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेल में हमारे युवाओं द्वारा नई ऊंचाईयों को छूने से देश गौरवान्वित है।

<u>खेलों में युवा</u>

एशियाई खेलों में भारत की उपलब्धियों उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 'एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक की सर्वाधिक संख्या में पदक जीते हैं जो बढ़े हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है।' केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि शतरंज के दिग्गज और हमारे नम्बर वन रैंक के खिलाड़ी प्रज्ञानंद ने 2023 में वर्तमान शतरंज

वर्ल्ड चैंपियन मैगनस कार्लसन को कड़ी टक्कर दी। शतरंज में भारत की सफलता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 'आज भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं जबकि वर्ष 2010 में 20 से थोड़े अधिक ग्रैंड मास्टर हुआ करते थे।

<u>तकनीक प्रेमी युवाओं के लिए कोष</u>

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस कोष के जरिए दीर्घकालिक वित्त पोषण अथवा पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दोनों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकनीक प्रेमी हमारे युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा। आज ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है जो युवा शक्ति और प्रौद्योगिकी को जोड़ें। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि इस कोष से निजी क्षेत्र अधिकांशत: नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहल को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित होगा।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई-11

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

पिछले एक दशक में प्रत्यक्ष कर संग्रह तीन गुना से भी अधिक बढ़ गया है और रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 2.4 गुना हो गई है: केन्द्रीय वित्त मंत्री

***

रिटर्न की प्रोसेसिंग में लगने वाला औसत समय वर्ष 2013-14 के 93 दिनों से काफी घटकर अब केवल 10 दिन रह गया है

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली...

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा, 'पिछले एक दशक में प्रत्यक्ष कर संग्रह तीन गुना से भी अधिक बढ़ गया है और रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 2.4 गुना हो गई है।' वित्त मंत्री ने करदाताओं को आश्वस्त किया कि उनके कर योगदान का व्यापक उपयोग देश के विकास और देशवासियों के कल्याण के लिए किया गया है। उन्होंने करदाताओं के व्यापक सहयोग के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की।

श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत कर दरों को घटा दिया गया है और इसके साथ ही उन्हें तर्कसम्मत बना दिया गया है। 7 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं पर अब कोई कर देनेदारी नहीं है, जो कि वित्त वर्ष 2013-14 में महज 2.2 लाख रुपये ही थी। खुदरा व्यवसाय के लिए अनुमानित कराधान की आरंभिक सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी तरह अनुमानित कराधान के योग्य माने जाने वाले प्रोफेशनलों के लिए संबंधित आरंभिक सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख

रुपये कर दिया गया। इसके साथ ही मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया और कुछ विशेष नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले पांच वर्षों में सरकार का फोकस करदाताओं को दी जाने वाली सेवाओं को बेहतर करने पर रहा है। उन्होंने कहा, '**फेसलेस आकलन और अपील** की शुरुआत करने के साथ ही अत्यंत पुरानी क्षेत्राधिकार आधारित आकलन प्रणाली अब पूरी तरह से बदल गई है जिससे इसमें दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही काफी हद तक बढ़ गई है।'

श्रीमती सीतारमण ने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि अद्यतन आयकर रिटर्न, एक नए फॉर्म 26एएस और पहले से ही भरे टैक्स रिटर्न की शुरुआत करने से टैक्स रिटर्न भरना अब और भी ज्यादा सरल एवं आसान हो गया है जिसके परिणामस्वरूप **रिटर्न की प्रोसेसिंग में लगने वाला औसत समय वर्ष 2013-14 के 93 दिनों से काफी घटकर इस वर्ष महज 10 दिन रह गया है** जिससे रिफंड अब और भी तेजी से करना संभव हो गया है।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई -12

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

*

राज्यों के एसजीएसटी राजस्व में तेज उछाल, जीएसटी पश्चात अवधि में 1.22 रहा

*

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी से उपभोक्ता सर्वाधिक लाभान्वित

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली...

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि भारत में अत्यंत विभाजित अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एकीकृत करके व्यापार और उद्योग पर अनुपालन का बोझ जीएसटी आने से कम हो गया है।

वित्त मंत्री ने कहा, "एक अग्रणी परामर्शदाता कंपनी द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 94 प्रतिशत शीर्ष उद्योगपति जीएसटी में हुए परिवर्तन को व्यापक स्तर पर सकारात्मक मानते हैं और सर्वेक्षण में प्रश्नों के उत्तर देने वाले 80 प्रतिशत प्रतिभागियों ने स्वीकार किया है कि इससे आपूर्ति श्रृंखला बेहतर हुई।" जीएसटी का कर आधार बढ़कर दोगुना हुआ और इस वर्ष औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर लगभग दोगुना यानी 1.66 लाख करोड़ रुपये हो गया।

राज्यों के राजस्व में वृद्धि का संकेत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को जारी किए गए मुआवज़े सहित राज्यों के एसजीएसटी राजस्व का तेज उछाल वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक

जीएसटी के बाद की अवधि में 1.22 रहा। जबकि वर्ष 2012-13 से 2015-16 की जीएसटी पूर्व के चार वर्षों में राजस्व टैक्स में उछाल केवल 0.72 था। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इन बात पर जोर देते हुए कहा कि जीएसटी से उपभोक्ता सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक तंत्र और करों में कमी के कारण अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आई है।

नेशनल टाइम रिलीज स्टडीज़ का जिक्र करते हुए मंत्री महोदया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए उठाये गए कदमों से वर्ष 2019 से अब तक के चार वर्षों के दौरान इनलैंड कंटेनर डिपो में आयात जारी करने की समयावधि 47 प्रतिशत कम होकर केवल 71 घंटे रह गई। एयर कार्गो परिसरों में 28 प्रतिशत कम होकर 44 घंटे और बंदरगाहों में 27 प्रतिशत कम होकर 85 घंटे रह गई।

**.*

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई/13

अंतरिम बजट - 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
****

सरकार 'वर्ष 2014 तक के आर्थिक हालात और मौजूदा स्थिति' पर श्वेत-पत्र लाएगी

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली --------

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार ने बागडोर संभाली थी, तब अर्थव्यवस्था को चरण-दर-चरण दुरुस्त करने और शासन प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त की मांग थी कि लोगों की उम्मीदें जगें, निवेश आकर्षित किया जाए और अति आवश्यक सुधार के लिए समर्थन जुटाया जाए। सरकार ने 'राष्ट्र प्रथम' के मजबूत विश्वास के साथ इसे सफलतापूर्वक हासिल किया।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने तब की और अब की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि उन वर्षों के संकटों से पार पा लिया गया है और हमारी अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास के साथ उच्च टिकाऊ विकास की राह पर बढ़ चली है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार अर्थव्यवस्था पर सदन के पटल पर श्वेत पत्र पेश करेगी, ताकि ये पता चल सकें कि वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र का मकसद उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीखना है।

शासन, विकास और निष्पादन,श्रीमती सीतारमण ने कहा कि शासन के अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड, विकास एवं प्रदर्शन, प्रभावी प्रदायगी और 'जन कल्याण' ने सरकार को लोगों का भरोसा, विश्वास और आशीर्वाद दिलाया है। इससे पता चलता है कि आने वाले वर्षों और दशकों में नेक इरादे, सच्ची लगन और भरपूर प्रयासों से 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, चाहे इसके लिए जितना भी जतन करना पड़े।

***

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तन *'विकसित भारत'* के लक्ष्य के सामने एक बड़ी चुनौती

****

जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली...

किया,

वर्ष 2047 तक विकसित भारत और अमृत काल पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तन द्वारा विकसित भारत के लक्ष्य के समक्ष बड़ी चुनौती की बात कही है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आगे कहा कि इस समिति को *'विकसित भारत'* के लक्ष्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों का संपूर्ण रूप से निराकरण करने के लिए सिफारिशें करने का अधिदेश दिया जाएगा।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई -

अंतरिम बजट – 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की

नए मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न विभागों में वर्तमान अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को उपयोग में लाया जाएगा

मौजूदा अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करने और मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में सिफारिश के लिए समिति का गठन किया जाएगा

आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवर

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली --------

वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए और युवा शक्ति पर ध्यान देने के साथ केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव किया।

ये नये मेडिकल कॉलेज विभिन्न विभागों में मौजूदा अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे के निरीक्षण और जरूरी सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल युवाओं के लिए डॉक्टर बनने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार लाया जा सकेगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यह भी प्रस्ताव किया कि आशा, आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायकों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई-16

अंतरिम बजट – 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

'नारी शक्ति' पर जोर, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण की घोषणा की

****

सरकार माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं में तालमेल स्थापित करेगी

****

डिजिटल इंडिया पहल को और मजबूती देने के लिए नया यू-विन प्लेटफॉर्म

****

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली --------

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने और नारी शक्ति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि सरकार माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं में तालमेल स्थापित करेगी।

सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी पात्र श्रेणियों के बीच इस टीकाकरण को बढ़ावा देगी।

माताओं एवं शिशुओं की देखरेख वाले विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तालमेल स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने आगे कहा कि बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर प्रारंभिक बाल्यवस्था देखरेख एवं विकास के

लिए 'सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0' के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पोषण की डिलीवरी, शुरुआती शिशु देखभाल एवं विकास में सुधार होगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया कि एक नया यू-विन प्लेटफॉर्म देशभर में तेजी से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग टीकाकरण के प्रबंधन और मिशन इंद्रधनुष के तहत प्रयासों को आगे बढ़ाने में किया जाएगा।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई-17

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा- सरकार गरीबी को परास्त करने के लिए *सबका साथ* के माध्यम से निर्धनों को सशक्त बना रही है

***

पीएम जन-धन योजना, पीएम स्वनिधि योजना और पीएम जन-मन योजना के जरिए होने वाले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लोगों के सशक्तिकरण के दस्तावेज

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गरीब कल्याण को देश के कल्याण के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि हम निर्धन लोगों के सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं।

लोकसभा में आज अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि हकदारियां देकर गरीबी से निपटने के लिए पहले के उपायों से बहुत ही मामूली परिणाम ही प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि जब गरीब विकास कि प्रक्रिया में सशक्त भागीदार बन जाते हैं, तो उनकी सहायता करने में सरकार की क्षमता भी कई गुणा बढ़ जाती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 'सबका साथ' मंत्र के साथ बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से छुटकारा दिलाया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस तरीके से सबल बनाए गए लोगों की ऊर्जा और उत्साह की सहभागिता से अब हमारी सरकार के प्रयासों को भी बल मिल रहा है। इससे वास्तव में वे गरीबी से ऊपर उठ रहे हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये का 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' करने से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। यह लाभ पूर्व में व्याप्त धन के लीकेज को रोककर सुनिश्चित किया गया है। सरकार की इस बचत से 'गरीब कल्याण' के लिए और अधिक निधियां प्रदान करने में सहायता मिली है।

गरीबों के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई योजनाओं का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी-पटरी

विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान की गई है। इनमें से दो लाख 30 हजार रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं ने तीसरी बार ऋण प्राप्त किया है।

श्रीमती सीतारमण ने पीएम-जनमन योजना को गरीबों के सशक्तिकरण का एक प्रमुख उपाय बताते हुए कहा कि यह योजना विशेष रूप से उन कमजोर जनजातीय वर्गों तक पहुंची है, जो अब तक विकास के दायरे से बाहर रहे हैं।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई-18

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

पांच एकीकृत एक्वापार्कों की स्थापना की जाएगी

***

वर्ष 2013-14 से सी-फूड का निर्यात दोगुना हुआ

***

एक्वाकल्चर उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात को दोगुना कर 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने और 55 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना में तेजी लाई जा रही है

***

ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए नई जलवायु गतिशील योजना आरंभ की जाएगी

***

डेयरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली...

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पांच एकीकृत एक्वापार्कों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार थी जिसने मछुआरों की सहायता करने के महत्व को महसूस करते हुए मत्स्य क्षेत्र के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। इसका परिणाम अन्तर्देशीय और एक्वाकल्चर उत्पादन दोनों के दोगुना होने के रूप में आया हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने रेखांकित किया कि 2013-14 से सी-फूड का निर्यात भी दोगुना हो गया है।

उन्होंने घोषणा की कि (i) एक्वाकल्चर उत्पादकता को प्रति हैक्टेयर वर्तमान 3 से बढ़ा कर 5 टन करने (ii) निर्यात को दोगुना कर 1 लाख करोड़ रुपये तक पँहुचाने और निकट भविष्य में 55 लाख रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी।

ब्लू इकोनॉमी 2.0

ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए जलवायु के अनुकूल कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत और बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ, पुनःस्थापन एवं अनुकूलन उपायों और तटीय एक्वाकल्चर और मारिकल्चर की एक योजना शुरू की जाएगी।

डेयरी विकास

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि डेयरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुरपका रोग को नियंत्रित करने के प्रयास पहले से चल रहे हैं। उन्होंने कहा "भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है लेकिन देश में दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है"। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण एवं पशुपालन के लिए अवसंरचना विकास निधि जैसी मौजूदा योजनाओं की सफलताओं पर आधारित होगा।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई -19

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 'अमृत काल' के लिए रणनीति पेश की

***

एमएसएमई के लिए समय पर और पर्याप्त वित्तीय साधनों, सुसंगत प्रौद्योगिकियों एवं उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करना सरकार की एक नीतिगत प्राथमिकता है

***

सरकार 'पंचामृत' लक्ष्यों के अनुरूप सतत रूप से उच्च और अधिक संसाधन-कुशल आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए काम करेगी; साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगी

***

'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के सिद्धांत के अनुसरण में सरकार अगली पीढ़ी के सुधारों पर काम करेगी, और राज्यों एवं हितधारकों के साथ सहमति कायम करेगी

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए 'अमृत काल' की रणनीति सामने रखी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए समय पर और पर्याप्त वित्तीय साधनों, सुसंगत प्रौद्योगिकियों और उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकता है ताकि उनका विकास हो सके और वे वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बन सकें। विनियामकीय परिवेश को उनके विकास के अनुरूप बनाना इस नीति का एक महत्वपूर्ण घटक होगा।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हमारी सरकार 'पंचामृत' लक्ष्यों के अनुरूप सतत रूप से उच्च और अधिक संसाधन-कुशल आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए काम करेगी।" उन्होंने कहा कि इससे उपलब्धता, पहुंच और मूल्य के लिहाज से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के सिद्धांत के अनुसरण में सरकार अब अगली पीढ़ी के सुधारों को अपने हाथ में लेगी, और कारगर क्रियान्वयन के लिए राज्यों और हितधारकों के साथ सहमति बनाएगी।

उन्होंने कहा, " सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी, जिससे विकास को गति और स्थायित्व मिले, समावेशी और सम्पोषणीय विकास

सुविधाजनक हो। साथ ही, उत्पादकता में सुधार हो, सभी के लिए अवसरों का सृजन हो, उनकी क्षमताएं बढ़ाने में मदद मिले और निवेश बढ़ाने तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को तैयार करने में योगदान किया जा सके।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए आकार, क्षमता, कौशल और विनियामकीय संरचना की दृष्टि से वित्तीय क्षेत्र को तैयार करेगी।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई-20

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, भारत और अन्य देशों के लिए एक रणनीतिक और आर्थिक परिवर्तनकारी पहल

***

2014-23 के दौरान एफडीआई अंतर्प्रवाह 596 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा

***

'पहले भारत का विकास' की भावना से द्विपक्षीय निवेश संधियों पर की जा रही है वार्ता

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि हाल ही में घोषित भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, भारत और अन्य देशों के लिए भी एक रणनीतिक और आर्थिक परिवर्तनकारी पहल है। संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री ने

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों का उल्लेख किया जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा, "*इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था।*"

वैश्विक संदर्भ का उल्लेख करते हुए, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भू-राजनैतिक दृष्टि से, वैश्विक मामले युद्धों और विवादों के कारण और अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण, स्वदेश में और मित्र देशों के यहां उद्योग स्थापित करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं के अस्त-व्यस्त होने और बिखरने तथा महत्वपूर्ण खनिजों एवं प्रौद्योगिकियों के लिए प्रतिस्पर्धा होने से पुनर्नियत हो रहा है। कोविड महामारी के बाद एक नई विश्व व्यवस्था उभर कर सामने आ रही है।

मंत्री महोदय ने कहा कि भारत ने दुनिया के लिए अत्यन्त मुश्किल समय के दौरान जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरें, निम्न विकास, अत्यधिक लोक ऋण, निम्न व्यापारिक विकास, और जलवायु संबंधी चुनौतियों से जूझ रही थी। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी ने दुनिया के लिए खाने-पीने, उर्वरक, ईंधन और वित्तीय साधनों का संकट उत्पन्न कर दिया था, जबकि भारत अपनी राह बनाने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि देश ने आगे बढ़ने का रास्ता सुझाया और उन वैश्विक समस्याओं के समाधानों के लिए सहमति बनाई।

निवेश को प्रोत्साहन

मंत्री महोदय ने कहा कि 2014-23 के दौरान एफडीआई अंतर्प्रवाह 596 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा था। यह एफडीआई का स्वर्णिम युग है और यह 2005-14 के दौरान हुए एफडीआई अंतर्प्रवाह से दोगुना है। उन्होंने कहा कि सतत विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने विदेशी साझेदारों के साथ 'पहले भारत का विकास' की भावना से द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता कर रहे हैं।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई/21

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कर्तव्य काल के रूप में अमृत काल पर जोर दिया

***

आर्थिक प्रबंधन और सुशासन के बल पर हम वर्ष 2014 से पहले के दौर की प्रत्येक चुनौती से उबरे

पूर्ण बजट में सरकार *'विकसित भारत'* के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी

विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों को 75,000 करोड़ का पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा

जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा

सरकार, अधिक आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने सहित आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के तीव्र विकास में राज्यों को सहायता देने के लिए तत्पर- केन्द्रीय वित्त मंत्री

सरकार का इस बात पर पूरा ध्यान है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और वहां के निवासी भारत के विकास के सशक्त संवाहक बनें

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली...

आज लोकसभा में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व और भारत की प्रगति पर उसके प्रभाव को रेखांकित करते हुए विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कर्तव्य काल के रूप में अमृत काल पर जोर दिया।

कर्तव्य काल के रूप में अमृत काल

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार उच्च वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और इसका विस्तार करने और लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने के लिये प्रतिबद्ध है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गणतंत्र के 75वें वर्ष में प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन को उद्धृत किया और कहा,''हम नई आकांक्षाओं, नई चेतनाओं और नए दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करें क्योंकि हमारा देश अनन्त संभावनाएं और अवसर प्रदान कर रहा है।" उन्होंने कहा यह हमारा 'कर्तव्य काल' है।

उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि हमारे आर्थिक प्रबंधन और सुशासन के बल पर हम वर्ष 2014 से पहले के दौर की प्रत्येक चुनौती से उबर गए हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इन प्रयासों ने हमारे देश को सतत् उच्च वृद्धि के संकल्प पथ पर आगे बढ़ा दिया है। यह सब हमारी सही नीतियों, सच्चे इरादों और उपयुक्त निर्णयों के कारण ही संभव हो सका है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जुलाई में, पूर्ण बजट में हमारी सरकार 'विकसित भारत' के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी।

विकसित भारत' के लिए राज्यों में सुधार

वित्त मंत्री ने कहा कि 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में संवृद्धि और विकास के अनेक समर्थकारी सुधार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने पचास वर्ष के ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में पचहत्तर हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है जिससे राज्य सरकारों तक संबंधित सुधारों की मदद पहुंचाई जा सके।

तीव्र जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। इस समिति को *'विकसित भारत'* के लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित इन चुनौतियों का संपूर्ण रूप से निराकरण करने के लिए सिफारिशें करने का अधिदेश दिया जाएगा।

आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों का तीव्र विकास

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत सरकार, अधिक आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने सहित आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के तीव्र विकास में राज्यों को सहायता देने के लिए तत्पर है।

पूर्वोत्तर विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर जोर देते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार इस बात पर पूरा ध्यान देगी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और वहां के निवासी भारत के विकास के सशक्त संवाहक बनें

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई -22

अंतरिम बजट 2024-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

अवसंरचना विकास परिव्यय में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि कुल 11,11,111 करोड़ रुपये निर्धारित

*****

प्रधानमंत्री गति-शक्ति के अंतर्गत चिन्हित रेलवे गलियारा परियोजना का शुभारंभ होगा

*****

मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नये हवाई अड्डों के विकास कार्य में तेजी आएगी

*****

मैट्रो रेल और नमो-भारत शहरी रूपांतरण के प्रेरक

****

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली...

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि अवसंरचना विकास परिव्यय में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और कुल 11,11,111 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा। उन्होंने कहा कि परिव्यय में वृद्धि से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में कई गुणा तेजी आएगी।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत पहचान किए गए तीन प्रमुख आर्थिक गलियारों का शुभारंभ किया जाएगा। ये तीन गलियारे हैं – (i) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, (ii) पत्तन संपर्कता गलियारा और (iii) अधिक यातायात वाला गलियारा। इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि रसद व्यवस्था में सुधार आएगा और लागत में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को "वंदे भारत" मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुना होकर 149 हो गयी है। उड़ान योजना के अंतर्गत और अधिक शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप देश की विमानन कंपनियां 1000 से अधिक नये वायुयानों की खरीद का आर्डर देकर विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही है। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नये हवाई अड्डों का विकास कार्य तीव्र गति से जारी रहेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि मेट्रो रेल और नमो भारत रेल प्रणाली विशेषकर बड़े शहरों के आवागमन उन्मुख विकास को बढ़ावा देगी।

**.*

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई/23

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

सरकार अमृत पीढ़ी - युवा वर्ग को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध : केन्द्रीय वित्त मंत्री

****

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 परिवर्तनकारी सुधार ला रही है : श्रीमती निर्मला सीतारमण

***

पीएम श्री स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है और बच्चों का समग्र तथा चहुंमुखी विकास किया जा रहा है

***

पीएम विश्वकर्मा योजना 18 व्यापारों में शामिल कलाकारों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक मदद कर रही है

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली --------

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि सरकार अमृत पीढ़ी-युवा वर्ग को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्रीमती सीतारमण ने जोर देते हुए कहा कि हमारी समृद्धि युवाओं को पर्याप्त रूप से साधन संपन्न करने और उन्हें सशक्त बनाने पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से परिवर्तनकारी सुधार लाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उदीयमान भारत के लिए पीएम स्कूल (पीएम श्री) में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है और बच्चों का समग्र तथा चहुंमुखी विकास किया जा रहा है।

श्रीमती सीतारमण ने स्किल इंडिया मिशन की उपलब्धियों को उजागर करते हुए कहा कि इस मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, 54 लाख युवाओं का कौशल-उन्नयन किया गया है तथा उन्हें दूसरे हुनर में कुशल बनाया गया है और 3000 नई आईटीआई स्थापित की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना 18 व्यापारों में शामिल कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक मदद प्रदान कर रही है।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में नए संस्थानों के अंतर्गत 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई-24

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा- सरकार नागरिक केंद्रित समावेशी विकास के लिए अधिक व्यापक जीडीपी यानी कि 'गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफार्मेंस' पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित किए हुए है

***

अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, चहुंमुखी विकास का असर सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है

***

सरकार ने 'नागरिक-प्रथम' तथा 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के दृष्टिकोण के साथ पारदर्शी, जवाबदेह, जन-केंद्रित और तत्पर विश्वास-आधारित प्रशासन सुनिश्चित किया हैः वित्त मंत्री

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से उच्च विकास करने के अलावा सरकार और अधिक व्यापक जीडीपी यानी कि 'गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफार्मेंस' पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित किए हुए है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि हमारी सरकार ने ‘नागरिक-प्रथम’ तथा ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के दृष्टिकोण के साथ पारदर्शी, जवाबदेह, लोक-केंद्रित और तत्पर विश्वास-आधारित प्रशासन को सुनिश्चित किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और निवेश की स्थिति शानदार नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता के साथ-साथ चहुंमुखी विकास का असर सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। बड़े पैमाने पर आर्थिक सुस्थिरता बाह्य क्षेत्र में भी नजर आती है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि लोगों का सशक्तिकरण हो रहा है। नागरिक अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सबल, साधनों से युक्त और समर्थ हो रहे हैं। वे अच्छा जीवन जी रहे हैं और बेहतर कमा रहे हैं तथा भविष्य के लिए और भी अधिक आकांक्षाएं रखे हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों की औसतन वास्तविक आमदनी पचास प्रतिशत बढ़ चुकी है। मुद्रास्फीति सामान्य बनी हुई है। विकास के कार्यक्रम और बड़ी परियोजनाएं प्रभावी रूप से तथा समय पर पूरी हो रही हैं।

आर्थिक प्रबंधन

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले दस वर्षों में इस बहुद्देशीय आर्थिक प्रबंधन से जन-केंद्रित

समावेशी विकास को बढ़ावा मिला है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं:-

(1) वास्तविक, डिजिटल या सामाजिक सभी प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर रिकार्ड समय में बनाए जा रहे हैं।

(2) देश के सभी हिस्से आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं।

(3) 21वीं सदी में उत्पादन का एक नया कारक डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है। यह अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने में सहायक है।

(4) वस्तु एवं सेवा कर से 'वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स' संभव हो पाया है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप कर आधार गहन और विस्तृत हुआ है।

(5) वित्तीय क्षेत्र को सशक्त करने से बचत, ऋण और निवेशों को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायता मिली है।

(6) जीआईएफटी-आईएफएससी और एकीकृत विनियामक प्राधिकरण, आईएफएससीए (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण) वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के उद्देश्य से सशक्त गेटवे तथा अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल वित्तीय सेवाएं तैयार कर रहे हैं।

(7) सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन से मुद्रास्फीति को पॉलिसी बैंड के अनुरूप बनाए रखने में मदद मिली है।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई-25

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

***

सरकार किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी अथवा चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपना मकान खरीदने या बनाने में सहायता के लिए योजना का शुभारंभ करेगी

***

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सरकार तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य प्राप्त करने के करीब

***

अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू होगा

***

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि सरकार किराए के मकानों अथवा झुग्गी-झोपड़ी या चाल और अनधिकृत

कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना का शुभारंभ करेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि कोविड से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इस योजना का कार्यान्वयन जारी रहा और सरकार तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य प्राप्त करने के करीब है। उन्होंने कहा कि परिवारों की संख्या में वृद्धि होने से बढ़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2047 तक देश को '*विकसित भारत*' बनाने के संकल्प के साथ सरकार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई/27

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

सरकार का फोकस चार जातियों - गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर केन्द्रित है : वित्त मंत्री

****

'सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक शासन पद्धति है'

****

लोगों की क्षमता बढ़ाना और उनका सशक्तिकरण है 'विकसित भारत' : वित्त मंत्री

****

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली --------

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार चार प्रमुख जातियों- 'गरीब', 'महिलाएं', 'युवा' और 'अन्नदाता' के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर विश्वास करती है। यह बात आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कही। उन्होंने कहा कि उनकी आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति तब होती है जब इन चारों जातियों से जुड़े लोग प्रगति करते हैं। इन चारों जातियों के लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में सरकारी सहायता की आवश्यकता है और उन्हें सरकारी सहायता मिल भी रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके सशक्तीकरण से और उनके कल्याण से देश आगे बढ़ेगा।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक शासन पद्धति है। उन्होंने आगे बताया कि भ्रष्टाचार में कमी से पारदर्शिता आई है और सभी पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार परिव्यय की चिंता न करके परिणामों पर जोर देती है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण से 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लोगों की क्षमता में वृद्धि करनी होगी और उन्हें सशक्त बनाना होगा।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई-28

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

****

सरकार तेज विकास दर के साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और इसका विस्तार करने एवं लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने को प्रतिबद्ध है

****

पीएम मुद्रा योजना, फंड ऑफ फंड्स, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टार्ट-अप क्रेडिट गारंटी जैसी योजनाएं युवाओं की उद्यमिता से जुड़ी आकांक्षाओं को बढ़ावा दे रही हैं

1 फरवरी, 2024

नई दिल्ली

सरकार तेज विकास दर के साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और इसका विस्तार करने और लोगों की आकांक्षाओं के मद्देनजर उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए यह बात कही।

कर्तव्य काल के रूप में अमृत काल

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसे कर्तव्य काल की शुरुआत बताते हुए भारतीय गणतंत्र के 75वें साल में प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का उल्लेख किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था, *"हम नई आकांक्षाओं, नई चेतनाओं और नए दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि हमारा देश अनंत संभावनाएं और अवसर प्रदान कर रहा है।"*

युवाओं की उद्यमिता की आकांक्षाओं को बढ़ाना

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत, 22.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के कुल 43 करोड़ ऋण मंजूर करने के साथ हमारे युवाओं की उद्यमिता से जुड़ी आकांक्षाओं को मजबूती दी गई है। इसके अलावा, फंड ऑफ फंड्स, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टार्ट-अप क्रेडिट गारंटी जैसी योजनाओं से भी हमारे युवा वर्ग को सहायता प्रदान की जा रही है और वे 'रोजगारदाता' भी बन रहे हैं।

***

एनबी/एमजी/पीआर/आरपी/हिंदी इकाई-29